सामाजिक बैंकिंग और वित्त - समावेशन में अवसर*

के.सी.चक्रवर्ती

श्री जेम्स क्रॅब्ट्री, मुंबई प्रतिनिधि, फाइनान्शियल टाइम्स और इस सत्र के संचालक, मेरे साथी पॅनलिस्ट श्री वाय.एम.देवस्थली, सीएमडी, एल एंड टी फाइनान्स; श्री अजय कुमार, सीएमडी कार्पोरेशन बैंक; श्री एम.वी.टांकसाले, सीएमडी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया; श्री आर.वी.वर्मा, सीएमडी, राष्ट्रीय आवास बैंक; श्री अजय देसाई, मुख्य वित्तीय समावेशन अधिकारी, यस बैंक और श्री लिओनार्डो रुबाटु, महा प्रबंधक, एक्रिया बैंका; प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यगण, देवियो और सज्जनो। आज दूसरे एफटी-यस बैंक अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सम्मेलन 2012 में उपस्थित रह कर इस सत्र के विषय 'सामाजिक बैंकिंग और वित्त - समावेशन में अवसर' पर अपने विचार आपके साथ बांटना मेरे लिए अत्यधिक प्रसन्नता और सम्मान की बात है। यह विषय बहुत ही प्रासंगिक है, विशेष रूप से मौजूदा वैश्विक आर्थिक संकट के संदर्भ में जिसके कारण यह माना जाता है कि वित्तीय प्रणाली के सामाजिक सरोकार में कमी आई और यह ऐसी दिशा में बढ़ी जो कि वास्तविक क्षेत्र से अलग थी। सामाजिक बैंकिंग और वित्तीय समावेशन चुनौती के साथ ही महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है जिससे एक व्यापक आधार की और स्थिर वित्तीय प्रणाली का निर्माण किया जा सकता है जो कि अंतत: वास्तविक क्षेत्र की वृद्धि और जनसामान्य की समग्र आर्थिक संपन्नता में महत्त्वपूर्ण योगदान करती है। 'वैश्विक बैंकिंग प्रणाली को सुसंगत करना' पर सम्मेलन की समग्र विषयवस्तु एकदम संगत है क्योंकि समावेशकता और सामाजिक उन्मुखता मुख्य स्तंभ होने चाहिए जिनके इर्द-गिर्द संकटोत्तर वैश्विक वित्तीय संरचना का विकास होता है। अत: मैं फाइनान्शल टाइम्स और यस बैंक का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस सम्मेलन में इस विषय को रखा और साथ ही आशा करता हूं कि आगे का सत्र बहुत उपयोगी सिद्ध होगा।

सामाजिक बैंकिंग क्या है?

2. सामाजिक बैंकिंग की बारीकियों पर कुछ कहने से पहले मैं इस बात पर संक्षेप में कहना चाहूंगा कि सामाजिक कारोबार और अधिक सूक्ष्मता से कहूं तो सामाजिक बैंकिंग क्या है। मेरी राय में ऐसा कोई भी कार्य जिसे समाज सामाजिक प्राथमिकताओं के अनुरूप नहीं पाता, वह कुछ समय के बाद लुप्त हो जाता है। अत: किसी भी कारोबार को बने रहने के लिए सामाजिक सरोकार रखना ही होता है। यह बात बैंकिंग कारोबार के संबंध में और अधिक लागू होती है क्योंकि यह कार्य अपने वित्तीय मध्यस्थ के कार्य के रूप में समाज, जिसके बीच यह कार्य होता है, की विकासात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप होना ही चाहिए। फिर भी बैंक वाणिज्यिक संस्थाएं होने के कारण उन्होंने लाभ प्राप्त करना ही चाहिए अन्यथा वे सक्षम नहीं रह पाएंगे या आघात नहीं सह पाएंगे। इसके साथ ही उन्हें सामाजिक सरोकार का ध्यान भी रखना होगा अन्यथा वे असंगत और अव्यवहार्य हो जाएंगे।

3. बैंकिंग कारोबार में वैश्विक रूप से मूल्यन प्रथाएं अपनायी गईं जिससे निर्धनों की सहायता से धनवानों को लाभ मिला। यह प्रणाली निर्धनों के लिए हानिकारक सिद्ध हुई क्योंकि इसमें उन्हें वित्तीय सेवाओं तक पहुंच के लिए उच्च लागत सहनी पड़ी या अनेक बार उन्हें अपनी निधीयन आवश्यकताएं पूरी करने के लिए महंगे अनौपचारिक स्रोतों का सहारा लेना पड़ा। इससे उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए वित्तीय प्रणाली का लाभ लेने के उन्हें उपलब्ध अवसर एकदम सीमित हो गए। अत: मेरा मत है कि सामाजिक बैंकिंग वह होती है जहां निर्धनों के लिए वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता के लिए धनवानों से सहायता मिले और जहां बैंकिंग कारोबार का लक्ष्य जनसामान्य को सेवा प्रदान करना हो, न कि उनका शोषण करने का।

4. इस प्रकार एक व्यापक दृष्टि से देखा जाए तो बैंकिंग कभी भी 'असामाजिक' नहीं हो सकती। अत: 'बैंकिंग' और 'सामाजिक

* डॉ.के.सी.चक्रवर्ती, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 15 अक्तूबर 2012 को मुंबई में द्वितीय एफटी-यस बैंक अंतरराष्ट्रीय बेंकिंग सम्मेलन में दिया गया सत्र का मुख्य भाषण। इस भाषण को तैयार करने में दिए गए सहयोग के लिए श्री आर.के.जैन और श्री बिपिन नायर को हार्दिक धन्यवाद।

बैंकिंग' अवधारणा को साथ-साथ प्रयोग किया जा सकता है। किंतु, चूंकि इस सम्मेलन के आयोजकों ने सामाजिक बैंकिंग और वित्त का विषय चुना है, अत: मैं 'सामाजिक' उपसर्ग का प्रयोग जारी रखूंगा, हालांकि मेरा दृढ़ विश्वास है कि बैंकिंग और वित्त को हमेशा सामाजिक ही होना चाहिए ताकि उनकी दीर्घकालिक व्यवहार्यता और सक्षमता बनी रहे।

सामाजिक बैंकिंग और वित्त - इस समय सर्वाधिक संगत

5. सामाजिक बैंकिंग और वित्त अब इतना अधिक संगत क्यों हो गया है? वैश्विक वित्तीय और आर्थिक संकट का वैश्विक रूप से लोगों पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। इस संकट के बाद अनेक लोग अपनी जीविका, आवास और बचत गंवा चुके थे। इस संकट का एक महत्त्वपूर्ण कारण यह था कि वित्तीय प्रणाली अपने हित के विस्तार में लगी हुई थी और वास्तविक क्षेत्र और अंतत: समाज हित से इसका संबंध कम हो गया था। सामाजिक बैंकिंग और वित्त की संगतता इस बात से भी पता चली कि बाजार की मुक्त शक्तियां वित्तीय प्रणाली में और विशेष रूप से समाज के दुर्बल वर्गों के हितों की रक्षा के संबंध में हमेशा ही लाभदायक सिद्ध नहीं होती। इसका कारण इन वर्गों के विरुद्ध सूचना की भिन्नता होता है जिससे वे गंभीर अलाभदायक स्थिति में रहते हैं।

6. संकटोत्तर काल में, सामाजिक बैंकिंग को विश्वभर में बहुत महत्त्व प्राप्त हुआ है। बैंकों द्वारा अपने कारोबारी हितों की रक्षा करने के साथ ही उनका समाज से सरोकार अनेक क्षेत्रों में विधायी और विनियामक माध्यमों से लागू किए गए विभिन्न उपायों में प्रतिबिंबित होता है। इन उपायों के पीछे यह तथ्य रहा है कि वित्तीय जगत की घटनाओं का प्रभाव वास्तविक क्षेत्र तक बढ़ सकता है जो कि जनसामान्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। इस प्रकार, वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और मजबूती सार्वजनिक चिंता का कारण है और यह इन उपायों से प्रकट होता है।

7. यह उल्लेखनीय है कि बैंक सामाजिक प्रणाली का अभिन्न हिस्सा हैं। वे मानव शक्ति, निधि, सहायक सेवाएं आदि जैसे संसाधन समुदाय से प्राप्त करते हैं जो कि बैंक सेवाओं के लिए ग्राहक भी होते हैं। इस प्रकार, बैंक अपने परिचालनों के लिए मुख्यत: समाज पर निर्भर होते हैं, अत: उनसे यह अपेक्षा करना उचित ही है कि वे सामाजिक बैंकिंग उपायों के माध्यम से समाज का ध्यान रखें।

सामाजिक बैंकों का इतिहास

8. ऐतिहासिक रूप से, पहले सामाजिक बैंकों की स्थापना इटली में 15वीं शताब्दी में हुई थी। उनका प्रारंभिक दायित्व मुद्रा की बचत करने की इच्छा रखने वालों और कारोबार के लिए धन की आवश्यकता वाले लोगों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने का था। भारत में, सहकारी बैंकों का इतिहास 1904 से शुरू होता है जब सहकारी ऋण समिति अधिनियम बना था। इस प्रकार, सामाजिक बैंकों का विचार नया नहीं है बल्कि एक ऐसा विचार है जो कि वैश्विक तौर पर और भारत में भी बहुत पहले उभरा था।

सामाजिक बैंकिंग की विशेषताएं

9. सामाजिक बैंकिंग और पारंपरिक वाणिज्य बैंकों के बीच महत्त्वपूर्ण अंतर यह है कि सामाजिक बैंकिंग का उद्देश्य भी लाभ कमाना होने के बावजूद यही एकमात्र उद्देश्य नहीं होता। सामाजिक बैंकिंग में समुदाय, जनकल्याण का भी ध्यान रखा जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि उनके कार्यों से जनसामान्य को लाभ पहुंचे। वे समाज को क्षति पहुंचाने वाले कार्यों की सहायता नहीं करेंगे बल्कि अपनी ऋण नीतियों से सामाजिक भलाई के कार्यों को प्रोत्साहित करेंगे।

10. सामाजिक बैंकिंग में ग्राहकों की आवश्यकताओं को बारीकी से समझा जाता है और उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप सर्वोत्तम उत्पाद विकसित किए जाते हैं। वे प्रौद्योगिकी की सहायता से मॉडलों के विकास की दिशा में कार्य करते हैं ताकि जनसामान्य को बैंकिंग सेवाएं उचित लागत पर मिल सकें। बैंकिंग के विस्तार से सामाजिक बैंकिंग समाज के अभावग्रस्त लोगों की आवश्यकताएं पूरी करने का प्रयास करती है।

सामाजिक बैंकिंग में निर्धनता पर ध्यान देने के लिए समावेशन को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है।

11. वैश्विक तौर पर लगभग 2.5 बिलियन लोगों की मूल बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच नहीं है। बैंकिंग सुविधा से वंचित लोग मुख्यत: विकासशील देशों में रहते हैं जो कि विश्व की कार्यशील जनसंख्या के लगभग आधे हैं। औपचारिक वित्तीय प्रणाली से बाहर रह जाने के कारण वे वैश्विक अर्थव्यवस्था में सहभागी नहीं हो पाते और इस प्रकार निर्धनता से बाहर निकलने के अवसरों का वे लाभ नहीं ले पाते।

12. बैंकों को गरीबी उन्मूलन में हित देखना चाहिए क्योंकि गरीबों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने से वे औपचारिक वित्तीय प्रणाली के साथ जुड़ेंगे और बैंकों के संभाव्य ग्राहक बनेंगे। सामाजिक बैंकिंग गरीबों की आवश्यकताओं के अनुसार कम लागत के नए उत्पाद तैयार करके उन्हें अपनी उद्यमो संबंधी तथा आपात जरूरतों के लिए उचित लागत के ऋण तक पहुंच बनाने में मदद कर सकती है। सामाजिक बैंकिंग वित्तीय शिक्षा पहलों के माध्यम से गरीबों के बीच वित्तीय उत्पादों और उनकी उपयोगिता के संबंध में जागरुकता उत्पन्न कर सकती है। बैंक प्रशिक्षण और परामर्श कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबों को ऋण हेतु पात्र बनने में भी सहायता कर सकते हैं।

अब मैं भारत में सामाजिक बैंकिंग की पहलों के संबंध में कुछ कहना चाहूंगा।

वित्तीय समावेशन के रूप में सामाजिक बैंकिंग - भारतीय अनुभव

13. भारत में सामाजिक बैंकिंग की शुरुआत सहकारी बैंकिंग आंदोलन, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना आदि जैसे उपायों के माध्यम से बहुत पहले ही गई थी, किंतु देश की व्यापक जनसंख्या और बैंकिंग सेवाओं के अभाव के कारण उनकी सफलता बाधित हुई थी। इस रुकावट से उपयुक्त प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही हटाया जा सकता है और इसीलिए पिछले दशक में प्रौद्योगिकी के विकास से देशमें वित्तीय समावेशन को भारी प्रोत्साहन मिला और समावेशक बैंकिंग पर काफी बल दिया गया।

14. भारत में समावेशक वृद्धि: प्रमुख लक्ष्य

- ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में समावेशक वृद्धि को प्रमुख नीतिगत लक्ष्य रखा गया। योजना के दस्तावेज में उल्लेख किया गया कि आर्थिक विकास, और विशेष रूप से 1990 दशक के मध्य के बाद, समावेशक नहीं था। 2003-04 और 2007-08 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की दर उच्च रहने के बावजूद यह बेरोजगारी और गरीबी को उपयुक्त कम स्तर तक नहीं ला पाई। इस प्रकार, ग्यारहवीं योजना के दस्तावेज में नीतियों की इस प्रकार पुनर्रचना करने का प्रयास किया गया कि वृद्धि तेज, व्यापक-आधारित और समावेशी हो। समावेशक वृद्धि के विचार में शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में व्यापक निवेश पर बल दिया गया।
- सामान्य तौर पर, नीति में आय और रोजगार के अवसर बढ़ाने और कृषि तथा लघु उद्योगों के विकास जैसे वृद्धि को अधिक समावेशक बनाने वाले कार्यक्रमों के वित्तपोषण पर बल देना है।
- यह स्वीकार किया गया था कि इन उद्देश्यों को पूरा करने में, विशेष रूप से कृषि की ओर प्रवाहित ऋण प्रवाह में वृद्धि की सहायतार्थ उपयुक्त इंफ्रास्ट्रक्चर/विस्तार सहायता देने में राज्य सरकारों की भूमिका महत्त्वपूर्ण होगी।

बहु संस्था दृष्टिकोण

15. भारत में वित्तीय समावेशन के लिए बहु संस्था दृष्टिकोण विद्यमान है।

- वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) को अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय समावेशन और वित्तीय शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने का दायित्व दिया गया है।
- भारत में जारी वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को और अधिक मजबूत करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एक उच्च स्तरीय **वित्तीय समावेशन सलाहकार समिति** का गठन किया है। समिति के सदस्यों के सामूहिक कौशल और अनुभव का उपयोग एक व्यवहार्य और मजबूत बैंकिंग सेवा सुपुर्दगी मॉडल के विकास का मार्ग बनाने के लिए किया जाएगा जिससे वित्तीय समावेशन और वित्तीय स्थिरता का साथ-साथ चलना सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त विनियामकीय संरचना का सुझाव देने के लिए और बैंकिंग नेटवर्क से बाहर रह गए ग्रामीण और शहरी ग्राहकों के लिए उत्पाद और प्रक्रिया के विकास के लिए पहुंच योग्य और उपयुक्त लागत पर वित्तीय सेवाएं प्राप्त हो सकें।
- रिज़र्व बैंक सहित वित्तीय क्षेत्र के विनियामक वित्तीय समावेशन मिशन के प्रति पूर्णत: प्रतिबद्ध हैं।

वित्तीय समावेशन के लिए अब तक क्या किया गया है

16. भारत में वित्तीय समावेशन के लिए अब तक किए गए कुछ उपाय:

- दूरस्थ गांवों में घरों तक कम लागत की बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आईसीटी आधारित कारोबार कारेस्पांडेट (बीसी) मॉडल लागू किया जा रहा है।

- अप्रैल 2010 से प्रारंभ करते हुए 3 वर्ष की बोर्ड अनुमोदित बैंकों की वित्तीय समावेशन योजनाएं भारिबैं की सूक्ष्म निगरानी में लागू की जा रही हैं।
- 2000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों को मार्च 2012 तक कवर की योजना बनाकर सफलतापूर्वक लागू की गई। 2000 से कम जनसंख्या वाले गांवों को कवर करना सुनिश्चित करने की योजना पर कार्य जारी है।
- बैंकों द्वारा नई शाखाओं में से कम-से-कम 25 प्रतिशत शाखाएं बैंक रहित ग्रामीण क्षेत्र में खोलना अनिवार्य।
- सभी एकल लोगों के लिए आधारभूत बचत बैंक जमा खाते की शुरूआत।
- छोटे खातों के लिए केवाईसी दस्तावेजों की आवश्यकता काफी सरल की गई।
- इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण और एफआईपी के बीच समन्वय के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए।
- बैंकों के लिए मूल्यन को पूर्णत: मुक्त किया गया। अग्रिमों पर ब्याज दरों को पूर्णत: अविनियमित किया गया।

17. भारिबैं द्वारा अपनाया गया दृष्टकोण - कुछ विशेषताएं

- भारत में, हमने वित्तीय समावेशन के लिए बैंक की अगुवाई वाला मॉडल अपनाया है जिसमें प्रौद्योगिकी काफी महत्त्वपूर्ण होती है। वित्तीय समावेशन की पहलें आईसीटी आधारित होंगी और नए सुपुर्दगी मॉडलों का प्रयोग करेंगी जिनका विकास बाजार सहभागियों को अपनी आवश्यकतानुसार करना होगा।
- हमारे अनुभव से पता चलता है कि वित्तीय समावेशन का लक्ष्य पूरा करने का कार्य मुख्य धारा की बैंकिंग संस्थाएं ही अच्छी तरह से का पा रही हैं क्योंकि इस संबंध में उपयुक्त उत्पाद प्रस्तुत करने की क्षमता उन्हीं के पास है।
- मोबाइल कंपनियों आदि जैसे अन्य सहभागियों को बैंकों के साथ मिलकर सेवाएं देने की अनुमति दी गई है।
- हम इस बात को मानते हैं कि हमारे वित्तीय समावेशन के प्रयासों में प्रौद्योगिकी बहुत महत्त्वपूर्ण है। प्रौद्योगिकी का उपयोग वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने और साथ ही इन सेवाओं की लागत घटाने के लिए किया जाना चाहिए। शुरुआत के रूप में, हमने इस बात पर जोर दिया है कि आरआरबी सहित सभी बैंक शाखाएं सीबीएस पर होनी चाहिए। हमने वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल, हस्तधारित उपकरण, स्मार्ट कार्ड, माइक्रो एटीएम, किओस्क आदि सहित मल्टी चैनल दृष्टिकोण को प्रोत्साहन दिया है। किंतु फ्रंट-एंड उपकरणों को बैंक सीबीएस प्रणालियों से समन्वित करने की आवश्यकता है।

कवरेज

किसी गांव को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध होना तब माना जाता है जब वहां कोई बैंक शाखा होती है या बीसी रहता है या वहां जाते रहता है।

उपलब्धता

बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता का अर्थ कम-से-कम चार उत्पादों की उपलब्धता है: i) ओवरड्राफ्ट सुविधा सहित आधारभूत बचत बैंक जमा खाता (पहले इसे नो फ्रिल खाता कहा जाता था)। ii) इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण के लिए विप्रेषण उत्पाद और अन्य विप्रेषण। iii) एक विशुद्ध बचत उत्पाद, आदर्शत: आवर्ती या परिवर्तनीय आवर्ती जमा। iv) उद्यमशीलता क्रेडिट, जैसे कि जनरल क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड।

सामाजिक बैंकिंग के सामने चुनौतियां

18. सामाजिक बैंकिंग की धारणा को अपने अंतर्निहित गुणों के बावजूद अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बैंक जनसामान्य को उचित लागत पर बैंकिंग सेवाएं देने वाला कुशल कारोबारी/सुपुर्दगी मॉडल अब तक लागू नहीं कर पाए हैं। अनेक सुपुर्दगी मॉडलों का परीक्षण किया गया है किंतु कोई भी मॉडल स्थापित नहीं हो पाया। इसी प्रकार, अनेक वैकल्पिक प्रौद्योगिकी विकल्पों भी परीक्षण किया गया है। किंतु, ऐसा कोई भी विकल्प अब तक अंतिम रूप नहीं ले पाया है जो व्यापक मात्रा में कम मूल्य के लेनदेनों को कम लागत पर हैंडल कर सके। बैंकों को अपनी मूल्यन प्रथा को परिष्कृत करना पड़ेगा ताकि सामाजिक बैंकिंग के प्रयासों की व्यवहार्यता और निरंतरता को सुनिश्चित करते समय सामाजिक सरोकार का मूल लक्ष्य सुनिश्चित किया जा सके।

19. बैंक के सामाजिक बैंकिंग के उपाय लागू करने में बैंक के स्टाफ को संवेदनशील बनाना भी बड़ी चुनौती है क्योंकि इन उपायों के उद्देश्यों से संबंधित स्टाफ को परिचित कराना होगा। यह बात अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है क्योंकि जनसामान्य तक बैंकिंग सेवाएं वे ही पहुंचाते हैं और इस प्रकार बैंक की सामाजिक बैंकिंग को लागू करने में

उनकी भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है। बैंकों द्वारा अपनाए जा रहे नवोन्मेषी प्लेटफार्म के साथ प्रौद्योगिकीय समन्वय के अलावा स्टाफ के लिए व्यवहारात्मक उन्मुखीकरण आवश्यक है जिससे कि वे जरूरतमंद समूहों के साथ संपर्क रखकर उनका विश्वास जीत सकें।

भावी मार्ग

20. बैंकिंग प्रौद्योगिकी की शुरुआत से और यह बात समझ में आने से कि गरीब लोग भी बैंकेबल हैं, बैंकिंग सुविधाओं से वंचित लोगों के बैंकिंग प्रणाली में शामिल होने की संभावना बढ़ी है। वित्तीय समावेशन और सरकार के विकास कार्यक्रमों से देश में समग्र वित्तीय और आर्थिक विकास होने की संभावना है। अधिकतर विकासशील देशों के जैसे ही, बैंक रहित समूहों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने से समावेशक वृद्धि को प्रोत्साहन मिलने की आशा है।

21. नवोन्मेषी सुपुर्दगी माध्यमों का विकास करना हमारे वित्तीय समावेशन पहलों के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण होगा। विश्व में सफलता के ऐसे अनेक अनुभव हैं जहां बाजार के सहभागियों ने वित्तीय अलगाव की समस्या के समाधान के लिए प्रौद्योगिकी की सहायता से नवोन्मेषी मॉडल तैयार किए। उदाहरण के लिए, केन्या जैसे अनेक देशों में लोगों को वित्तीय सेवाओं तक पहुंच देने के लिए एम-पीईएसए मॉडल के माध्यम से मोबाइल फोन की सहायता ली गई। बहुत अधिक लोगों के पास मोबाइल फोन होने के बावजूद इस माध्यम की संभावना बैंक खातों में प्रकट नहीं होती। इसी प्रकार, विभिन्न देशों द्वारा सूक्ष्म वित्त, बैंकिंग एजेंट्स आदि का प्रयोग वित्तीय समावेशन की दृष्टि से काफी लाभदायक सिद्ध हुआ है।

22. भारत में, नीतिगत संरचना पहले से ही मौजूद है। किंतु वित्तीय सेवा प्रदाताओं द्वारा सेवाओं के प्रावधान के लिए सुपुर्दगी प्लेटफार्म और एक सक्षम कारोबारी मॉडल अब भी विकास होने की प्रक्रिया में है। बैंक अन्य भागधारकों और समाज के साथ मिलकर सामाजिक बैंकिंग के अपने मॉडल को स्थिर तथा उन्नत करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। पहले उल्लेख किए अनुसार, हम बैंक की अगुवाई वाले मॉडल के लिए प्रयास कर रहे हैं जिसमें व्याप्ति बढ़ाने और सेवा प्रदानगी की लागत घटाने के लिए प्रौद्योगिकी का सहारा लिया जाता है। हम किसी विशेष प्रौद्योगिकी पर जोर नहीं दे रहे हैं और बैंक किसी भी प्रौद्योगिकी का चुनाव कर सकते हैं। हम बैंकों को प्रोत्साहन देते हैं कि वे ऐसे मॉडल विकसित करें जो कि व्यवहार्य और दीर्घकालिक रूप से कार्य कर सकें।

समापन

23. वित्तीय संकट और लोगों के बीच बढ़ती बेचैनी, जैसी कि 'वाल स्ट्रीट पर कब्जा करो' और विश्वभर में हुए ऐसे ही आंदोलनों को ध्यान में रखते हुए आगे के सुधार उपायों में ऐसे कानूनों पर ध्यान दिया गया जिससे बैंकों की निवेश प्रथाओं और सट्टेबाजी पर नियंत्रण रहे। दीर्घावधि के संबंध में बेहतर दृष्टिकोण वह लगता है कि लाभ के लक्ष्य के साथ ही बैंकिंग प्रथाएं सामाजिक और नैतिक रूप से सभी हिस्सेदारों की ओर उन्मुख होनी चाहिए। सामाजिक बैंकिंग मॉडल काफी मजबूत मॉडल के रूप में उभर सकता है जो कि वैश्विक वित्तीय प्रणाली को मौजूदा कुछ समस्याओं से बचा सकता है।

24. सामाजिक बैंकिंग के लिए बल दो दृष्टिकोणों से आ सकता है -एक, विधिक और विनियामक अपेक्षाओं के माध्यम से। किंतु इस मॉडल में सामाजिक बैंकिंग पर मात्र अनुपालन की दृष्टि से ध्यान दिया जाएगा। दूसरे विकल्प में, जिसमें अधिक संभावना है, बाजार के सहभागियों को यह समझना आवश्यक है कि सामाजिक बैंकिंग सक्षम कारोबारी अनुपात हो सकता है। इसके लिए, बैंकों को इस बात को पूर्णत: मानना होगा कि सामाजिक बैंकिंग उनके अपने हित में है और यह कि इस मॉडल को अपनाने से उनकी दीर्घकालिकता और वृद्धि सुनिश्चित होगी। इसे अच्छी तरह से पहचाना गया है कि बैंकों द्वारा स्वैच्छिक रूप से प्रयास किए बिना सामाजिक बैंकिंग को उच्च स्तरीय सक्षम विकल्प के रूप में स्थापित नहीं किया जा सकेगा। तदनुसार, भारत में हमने वित्तीय समावेशन का नेतृत्व बैंकों के पास रखने के लिए प्रोत्साहित किया है और यह कार्य बैंकों के बोर्डों द्वारा अपने बनाए लक्ष्यों के अनुसार विकसित किए गए वित्तीय समावेशन की योजना से मार्गदर्शित होगा।

25. जैसा कि नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त भूतपूर्व रशियन अध्यक्ष श्री मिखाइल गोर्बाचोव ने कहा है, बेहतर भविष्य के लिए शांति, गरीबी से लड़ाई, वैश्विक सामाजिक न्याय और सार्वजनिक धन वृद्धि

तथा पर्यावरण की सुरक्षा अनिवार्य है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के हमारे प्रयासों में सामाजिक बैंकिंग का योगदान महत्त्वपूर्ण होगा।

26. मैं फाइनान्शियल टाइम्स और यस बैंक को इस सम्मेलन के आयोजन के लिए बधाई देता हूं और मुझे यहां उपस्थित रहने का अवसर देने के लिए एक बार फिर से उन्हें धन्यवाद देता हूं। मुझे आशा है कि आज के पैनल के मेरे विद्वान साथी रुचिपूर्ण और प्रेरक चर्चा करेंगे और मुझे उम्मीद है कि इस सत्र में ऐसे विचार सामने आएंगे जिन पर वित्तीय बाजार के सहभागी, विनियामक और सिविल सोसायटी कार्य कर पाएंगे जिससे सामाजिक बैंकिंग एक दृढ़ विचार बनेगा।

धन्यवाद।

चुनिंदा संदर्भ

1. डॉ. के. सी. चक्रवर्ती, उप गवर्नर, भारिबैं द्वारा सेंट झेवियर्स कॉलेज में वित्तीय समावेशन पर 6 सितंबर 2011 को दिया गया भाषण।

2. डॉग जॉनसन, सेंटर फॉर माइक्रोफाइनान्स, 'वित्तीय समावेशन और सामाजिक अंतरण भुगतानों की सुपुर्दगी', 2010.

3. सामाजिक बैंकिंग और सामाजिक वित्त: आर्थिक संकट के उत्तर, स्प्रिंगर, न्यूयार्क, 2010.

4. ड्राफ्ट पंचवर्षीय योजना दस्तावेज (2007-12), योजना आयोग, नई दिल्ली, 2007.

5. डेनियल एम. स्विडलवस्की, पेरू विकास वित्त निगम, 'फाइनान्शियल इन्क्लूजन टू एड्रेस पॉवर्टी'।